रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14

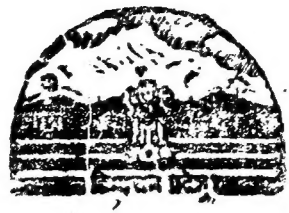

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बृहस्पतिवार, 30 अक्तूबर, 1986/8 कार्तिक, 1908

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन खेती एवं संरक्षण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 13 अगस्त, 1986

संख्या एफ0टी0एस0 (एफ0) 6-7/82-लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) में परिभाषित वन्य प्राणियों द्वारा की गई हानि का प्रार्थना-पत्र पर दावा किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं या परिवार के किसी सदस्य या आश्रित या उसके अपने पशु के लिए अनुदान सहायता प्राप्त करने हेतु निम्न शर्तों और अधिकतम दरों के अनुसार निम्न योजना को सहर्ष स्वीकार करते हुए सहायता प्रदान करने की स्वीकृति देते हैं ।

यह आदेश तुरन्त लागू होंगे ।

	रुपये
1. किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर	10,000
2. किसी व्यक्ति की स्थायी विकलांगता पर	5,000
3. किसी व्यक्ति के घायल होने पर	1,000
4. गायशाला में भैंस, गाय (जरसी गाय), बैल और खच्चर (व्यस्क) विशेष नस्ल की हानि पर ।	2,000

2306-राजपत्र/86-30-10-86—1190. मूल्य : 20 पैसे।

		रुपये
5.	जंगल में गाय, भैंस, बैल और खच्चर (व्यस्क) (विशेष नस्ल) की हानि पर	1,200
6.	गायशाला में गाय (स्थानीय नस्ल) की हानि पर	500
7.	जंगल में गाय (स्थानीय नस्ल) की हानि पर	300
8.	पशुशाला में बैल (स्थानीय नस्ल) की हानि पर	1,000
9.	जंगल में बैल स्थानीय नस्ल की हानि पर	500
10.	पशुशाला में अल्पायु की भैंस, गाय (जरसी) बैल तथा खच्चर (विशेष नस्ल की) हानि पर	200
11.	जंगल में अल्पायु की भैंस, गाय (जरसी) बैल तथा खच्चर (विशेष नस्ल) की हानि पर	150
12.	जंगल पशुशाला जहां भी हो, अल्पायु की भैंस, गाय (स्थानीय नस्ल) बैल तथा खच्चर स्थानीय नस्ल की हानि पर	100
13.	पशुशाला में भेड़ तथा बकरी की हानि पर	300
14.	जंगल में भेड़ तथा बकरी की हानि पर	150

1. वह मानव हानि के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट या घायल/विकलांग होने पर सरकारी संस्थान के चिकित्सा-अधिकारी से जैसा कि मामला हो, प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है ।

या

पशु हानि के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट पशु चिकित्सा अधिकारी से प्रस्तुत करता है ।

2. वह ग्राम पंचायत प्रधान/अध्यक्ष अधिसूचित क्षेत्र समिति/अध्यक्ष म्युनिसिपल कमेटी/कमिश्नर नगर निगम, कन्टोनमैन्ट बोर्ड क्षेत्र के चुने हुए सदस्य द्वारा प्राप्त प्रमाण-पत्र जिसमें वन्य प्राणी द्वारा वास्तव में हुई हानि का हवाला होगा तथा वन अधिकारी, जो वन परिक्षेत्राधिकारी, जो वन परिक्षेत्राधिकारी के पद से निम्न का न हो से सत्यापित करवा के प्रस्तुत करेगा ।

3. क्षेत्रीय मण्डलों/वन्य प्राणी मण्डलों के उप-अरण्यपाल वन मण्डलाधिकारी ऐसे दावों का निरीक्षण करेंगे और मुख्य वन्य प्राणी द्वारा की गई हानि की सीमा निर्धारित करेंगे और मुख्य वन्य प्राणी संरक्षक ऐसे मामलों के दावों को स्वीकृत करने के लिए अन्तिम निर्णायक अधिकारी होंगे ।

4. प्रार्थी, सहायता प्राप्त करने का अधिकारी तब होगा जबकि वह सम्बन्धित घटना की रिपोर्ट तीन दिन के समय की अवधि में नजदीकी वन परिक्षेत्राधिकारी/क्षेत्रीय वन परिक्षेत्राधिकारी या वन विभाग के किसी अन्य ऊंचे पद के अधिकारी को सूचित करें तथा सहायता प्राप्त करने के दावे को एक मास की अवधि में उप-अरण्यपाल/वन मण्डलाधिकारी और वन विभाग के क्षेत्रीय तथा वन्य प्राणी दोनों में से किसी एक ऊंचे पद के अधिकारी के पास आवेदन करें ।

5. यदि घरेलू पशुओं की हानि होगी तो उनके स्वामी को आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी :

6. जब हानि होने पर सहायता निम्न प्राथमिकता के आधार पर दी जायेगी :—

(अ) पत्नी या पति (जैसी भी स्थिति हो) ।

(ब) पुत्र, अविवाहित या तलाकशुदा पुत्रियां तथा पूर्व मृतक पुत्र के बच्चे (बराबर के हिस्सेदार) ।

(स) पुत्रियां (बराबर की हिस्सेदार) ।

(द) मृतक के उन पुत्रों व पुत्रियों के बच्चे (अर्थात् पौत्र व नाती) जिनका मृतक से पहले ही स्वर्गवास हो गया हो (बराबर के हिस्सेदार) ।

(ध) माता या पिता ।

यदि उपरोक्त में से कोई भी न हो तो मृतक का निकट सम्बन्धी उस सम्पदा का हकदार होगा।

मृतक भाई या बहनों के भाई या बहनें या बच्चे (बराबर के हकदार)।

आदेशानुसार,
एस० के० चौहान,
वित्त आयुक्त एवं सचिव (वन)।

FOREST FARMING AND CONSERVATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 13*th August*, 1986

No. FTS (F) 6-7/82-Loose.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to accord sanction to the following schemes for the grant of relief to person who on application claims relief on account of damage caused by Wild Animals as defined in Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) to himself or member of his family, or dependents or his own cattle, on the following conditions and maximum rates mentioned below. These orders will come into force with immediate effect:—

		Rs.
(*i*)	In case of death of human beings	10,000
(*ii*)	In case of permanent disability to human beings	5,000
(*iii*)	In case of injury to human beings	1,000
(*iv*)	Loss of Buffaloe, cow (Jersey cross) Ox and Mule (Adults) (Special breed) in cow-shed.	2,000
(*v*)	Loss of Cow, Buffaloe, Ox and Mule (Adults) (Special breed) in jungle	1,200
(*vi*)	Loss of Cow (Local breed) in Cow-shed	500
(*vii*)	Lose of Cow (Local breed) in Jungle	300
(*viii*)	Loss of Ox (Local breed) in shed	1,000
(*ix*)	Loss of Ox (Local breed) in Jungle	500
(*x*)	Loss of young ones of Buffaloe, Cow (Jersey) Ox and Mule (Special breed)in shed	200
(*xi*)	Loss of young ones of Buffaloe, Cow (Jersey) Ox and Mule (Special Breed) in Jungle.	150
(*xii*)	Loss of young ones of Buffaloe, Cow (Local breed) Ox and Mule (Local breed) in shed as well as in jungle.	100
(*xiii*)	Loss of Sheep and Goat in shed	300
(*xvi*)	Loss of Sheep and Goat in Jungle	150

(*i*) Production of postmortem report in case of loss of human life or injury/ disability certificate from the Medical Officer of a Government Institution as the case may be.

OR

Postmortem report from a Vety. Doctor in case of loss of cattle life.

(*ii*) Production of a certificate from the Pradhan Gram Panchayat/President Notified Area Committee/Chairman Municipal Committee/Commissioner, Municipal Corporation of the area or from the elected member of the

Cantonment Board area to the effect that loss was actually caused by wild animals duly verified by Forest Officer not below the rank of the Range Forest Officer.

(*iii*) The Deputy Conservator of Forests/Divisional Forest Officer of the Territorial Divisions/Wildlife Divisions shall be the authority to examine claims and extent of loss damage caused by the Wildlife and the Chief Wildlife Warden shall be the final authority to sanction such cases of claims.

(*iv*) The applicant shall be entitled for relief in case the report of incident is made to the nearest Range Officer, Territorial Range Officer or any other higher officer of the Forest Department within three days of the event and claims for relief is filed within a month with Deputy Conservator of Forests/Divisional Forest Officers and any other higher officer of the Forest Department both Territorial and Wildlife.

(*v*) The relief shall be granted in case of loss of cattle to the owner of the cattle.

(*vi*) The relief in case of loss of the human being shall be granted in the order of preference given below:—

(*a*) Wife or husband, as the case may be.

(*b*) Sons, unmarried or divorced daughters and children of predeceased son (Equal share).

(*c*) Daughters (Equal share).

(*d*) Grand Children being children of sons or daughters who died before him (Equal share).

(*e*) Father or Mother.

(*f*) Failing all above any other next of kin entitled to share in the estate.

(*g*) Brothers or sisters or children of the deceased brothers or sisters (equal share).

By order,
S. K. CHAUHAN,
Financial Commissioner-cum-Secretary.

कार्यालय उपायुक्त, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

शिमला-1, 24 अक्तूबर, 1986

संख्या पी0सी0 एच0-एस0एम0एल0(3)-20/85-9267-74.—मैं, जे0 पी0 नेगी, उपायुक्त, जिला शिमला, उन शक्तियों के अधीन जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 10 तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 19-बी के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिला शिमला के निम्न पंच के त्याग-पत्र को खण्ड विकास अधिकारी मशोबरा की सिफारिश के आधार पर तुरन्त स्वीकृत करता हूं :—

1. श्री ज्ञान चन्द — पंच, ग्राम पंचायत बायचड़ी, वार्ड नं0-1, कुटासनी, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला।

जे0 पी0 नेगी,
उपायुक्त।

Office of the District Magistrate Mandi, District Mandi, H.P.

NOTIFICATION

Mandi, the 23rd October, 1986

No. FDS. MND. K. OIL/83-9476-9574.—In supersession of this office Notification No. FDS. MND.K. OIL/83-1765-1854, dated 15-2-1986 and in exercise of the powers vested in me under section 3 of the K. Oil (Fixation of Ceiling Price) Order, 1970, I, S. Padamnabhan, District Magistrate, Mandi District, H. P. do hereby fix the wholesale and retailsale price of K. Oil at various places of Mandi District as under:—

FOR SUPPLIES RECEIVED FROM DAMTAL

Sr. No.	Name of Station	Wholesale rate including all taxes	Retailsale rate including taxes per litre
1.	Jogindernagar	2497.80	2.55
2.	Mandi	2541.10	2.61
3.	Pandoh	2554.80	2.66
4.	Nerchowk	2558.22	2.66
5.	Sundernagar	2565.36	2.63
6.	Slapper	2579.08	2.68
7.	Baggi	2557.76	2.66
8.	Chailchowk	2565.36	2.67
9.	Rewalsar	2559.34	2.66
10.	Sarkaghat	2588.16	2.65
11.	Jai Devi	2569.90	2.67
12.	Lad Bharol	2497.80	2.59
13.	Chauntra	2490.25	2.59
14.	Balichowki	2581.34	2.68
15.	Karsog	2633.71	2.74(if supplied to
16.	Jhungi	2596.51	2.70the dealers of
17.	Padhar	2593.47	2.70Mandi Distt).
18.	Pangana	2609.41	2.71
19.	Churag	2617.00	2.72
20.	Rohanda	2587.47	2.69
21.	Sandhole	2620.04	2.73
22.	Bagsaid	2585.10	2.69
23.	Thunag	2597.24	2.70
24.	Janjehli	2607.90	2.71
25.	Aut	2582.96	2.69
26.	Longni	2598.72	2.70
27.	Tihra	2601.78	2.71

CONDITIONS

1. Wholesale dealers will supply the K. Oil only to the authorised retailers and intimation of the tanker supplied at various places/parties may be sent to the Inspector, Food and Supplies, of the area as well as to the District Food and Supplies Controller, Mandi H. P.

2. The retailers where F.O.R. supplies are not being made by wholesale dealers shall be entitled to charge the actual incidental charges over and above rates from the nearest station for which rates have been approved.

3. The Kerosene oil will not be stored at any premises other than the place of business without the permission of the District Administration.

4. Each wholesaler shall prominently display the price and stocks of K. Oil on the price list at the entrance of his place of business and proper record of receipt and sale shall have to be maintained and produced before the Inspecting Officer on demand. The wholesalers are bound to issue cash memo for each sale of Kerosene Oil.

5. Any dealer selling or attempting to sell or abetting the sale of Kerosene Oil at rates higher than those fixed above or refusing to sell the Kerosene Oil without sufficient reasons shall be prosecuted under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955.

6. All wholesale dealers of Kerosene Oil will submit weekly/monthly statement partywise to the District Food and Supplies Controller, Mandi.

7. The sale of 20 litre Kerosene Oil at one time to a consumer will be treated as wholesale transaction and wholesale rate is to be charged from such consumer. Further no wholesale dealer will refuse any consumer for issuing K. Oil to the tune of 20 litres and above.

S. PADAMNABHAN,
District Magistrate, Mandi (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।